

चाहिए।

संपादकीय

गलत राह पर पाक

लोन और आर्थिक मदद की वजह से ही पाकिस्तान अभी तक दिवालिया होने से बचा हुआ है, लेकिन इसकी वजह से उस पर 269 बिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है, जबकि उसके मौजूदा बजट का आकार है केवल 63 बिलियन डॉलर।



पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20प्रतिशत का इजाफा किया है। इससे उसकी प्राथमिकता साफ हो जाती है कि उसके लिए अपनी जनता का कल्याण और विकास नहीं, भारत के खिलाफ आक्रामकता ज्यादा जरूरी है। यह बात और है कि बजट का 14.5प्रतिशत सिर्फ डिफेंस पर खर्च करके वह अपनी मुश्किलें ही बढ़ाएगा।

कर्ज पर गुजारा: लोन और आर्थिक मदद की वजह से ही पाकिस्तान अभी तक दिवालिया होने से बचा हुआ है, लेकिन इसकी वजह से उस पर 269 बिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है, जबकि उसके मौजूदा बजट का आकार है केवल 63 बिलियन डॉलर। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने की आदत ने पाकिस्तान को ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया है, जहां अब उसे अपने बजट का करीब आधा हिस्सा कर्ज की किस्तों और ब्याज भरने के लिए देना पड़ेगा। अब जो रकम बचती है, उसमें से भी लगभग एक तिहाई, 9.17 बिलियन डॉलर उसने डिफेंस के लिए रखा लिया है।

भारत से तुलना: इस्लामाबाद में नई दिल्ली के साथ होड़ करने की बेवैनी और उतावलापन है। लेकिन सच यही है कि इतने भारी खर्च के बावजूद भारत के 77 बिलियन डॉलर के डिफेंस बजट के सामने पाकिस्तान का रक्षा बजट बहुत मामूली है। हां, यह जरूर है कि यह होड़ उसे कर्ज, खासकर चीन के कर्ज

के जाल में और फंसा रही है। पाकिस्तान पर सबसे बड़ी देनदारी चीन की है, लगभग 15 बिलियन डॉलर।

चीन का फायदा: पाकिस्तान अपने लगभग 80 प्रतिशत सैन्य साजो-सामान और हथियार चीन से खरीदता है। चीन जे-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी पाकिस्तान को देने जा रहा है। यानी उसके सैन्य बजट का एक बड़ा भाग चीन की जेब में जाएगा। यही नहीं, शहबाज शरीफ सरकार ने बजट में कर्ज अदायगी के लिए जो रकम रखी है, उससे भी सबसे बड़ा हिस्सा चीन को मिलेगा। विडंबना है कि भारत के साथ टकराव के दौरान पाकिस्तान को चीनी डिफेंस सिस्टम की वजह से ही नुकसान और शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी।

आर्थिक मुश्किलें: पाकिस्तान को हथियार से ज्यादा रोजगार, निवेश और अन्न की जरूरत है। उसकी इकॉनमी एक अरसे से जड़ बनी हुई है। 2025 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2.7 प्रतिशत है। आर्थिक मोर्चे पर उसकी सबसे बड़ी खुशी यह है कि आईएमएफ ने हाल में एक नए बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान का बजट भारत की चिंताओं की पुष्टि करने के साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को भी आईना दिखाता है। ये संस्थाएं बार-बार भरोसा टूटने के बावजूद पाकिस्तान के किसी नए वादे के झांसे में आकर मदद देती रहती हैं। क्या अब वे सबक लेंगी?

ऐसा बताया गया है कि नया नियम फिलहाल सभी नए एअर कंडीशनर पर लागू होगा। यानी आने वाले दिनों में बाजार में उपलब्ध एअर कंडीशनर में तापमान 20 डिग्री से नीचे और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रखा जा सकेगा।

एअर कंडीशनर का नया नियम – न बहुत ठंडा, न बहुत गर्म, तय होगी तापमान की सीमा

अपने घर या कार्यालय को मनमर्जी के मुताबिक वातानुकूलित करने की प्रवृति अब लोगों को बदलनी होगी। क्योंकि, आने वाले दिनों में एसी (एअर कंडीशनर) की हवा को ज्यादा ठंडा करने का विकल्प ही मौजूद नहीं होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि केंद्र सरकार एअर कंडीशनर के तापमान का मानकीकरण करने वाली है। नए नियमों के तहत इसके तापमान को न्यूनतम 20 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में ही रखा जाएगा।

इससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। कई देशों में इस तरह के नियम पहले से लागू हैं। भारत में भी इसको लेकर काफी पहले से विचार किया जा रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी पहलू और सरकारी स्तर पर इच्छाशक्ति का अभाव इसमें रोड़ा बना हुआ था, पर अब सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए नए नियमों के मसविदे को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

वातानुकूलन के लिए तापमान का मानकीकरण भी जरूरी

देश में वातानुकूलन के लिए तापमान का मानकीकरण इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बिजली की मांग चरम पर



पहुंच जाती है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान एअरकंडीशनर और हवा को ठंडा करने वाले अन्य उपकरणों का होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वातानुकूलन के समय तापमान तय सीमा में रखा जाए तो देशभर में सालाना हजारों करोड़ यूनिट बिजली की बचत हो सकती है। इससे कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों पर भी दबाव कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी खासी कमी आएगी।

भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वैसे भी अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। जापान, इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में एअर कंडीशनर के तापमान को लेकर पहले से ही सख्त नियम लागू हैं। जापान में तापमान की सीमा 26 डिग्री, जबकि इटली और स्पेन में

23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखी गई है।

ऐसा बताया गया है कि नया नियम फिलहाल सभी नए एअर कंडीशनर पर लागू होगा। यानी आने वाले दिनों में बाजार में उपलब्ध एअर कंडीशनर में तापमान 20 डिग्री से नीचे और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रखा जा सकेगा। इसका एक फायदा यह भी होगा कि बिजली की खपत कम होने से बिल की राशि भी कम होगी। यानी समाज के मध्यम वर्ग के लिए सरकार का यह कदम राहत भरा होगा। घरों के अलावा सार्वजनिक भवनों, होटलों, माल, कार्यालयों, विपणन केंद्रों और कारों में लगे वातानुकूलन उपकरणों पर भी ये नियम लागू होंगे।

हालांकि, घरों में लगे पुराने एअरकंडीशनर को लेकर सरकार की ओर से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरे पहलू से देखा जाए तो कमरे में बहुत कम तापमान रखना स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रहने से सांस संबंधी समस्याएं, सर्दी-खांसी, जोड़ों में दर्द और त्वचा संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए 24-26 डिग्री का तापमान आदर्श होता है।

शिक्षा के नाम पर लूट बंद होगी, दिल्ली में स्कूल फीस पर कानून का शिकंजा

दिल्ली के निजी विद्यालयों में मनमाने तरीके से शुल्क बढ़ाए जाने पर सवाल उठते रहे हैं। अभी हाल ही में द्वारका में कई अभिभावकों ने सरकार की अनुमति के बिना एक विद्यालय पर शुल्क बढ़ोतरी का आरोप लगाया था। साथ ही दावा किया था कि बच्चों और उनके माता-पिता पर दबाव बनाने के लिए कुछ स्कूलों में अतिरिक्त कर्मी तैनात किए जाते हैं।

निजी विद्यालयों की निरंकुशता का मुद्दा अदालतों में भी उठता रहा है। ऐसा भी नहीं कि

शिक्षा निदेशालय को वस्तुस्थिति मालूम न हो। सवाल यह है कि निजी विद्यालयों को मनमानी करने की छूट किसने दी?

कौन लोग हैं जो इन्हें अब तक शह देते रहे हैं? लगातार शिकायतें मिलने पर दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा (पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन-2025) विधेयक पारित करने का निर्णय किया था, मगर किन्हीं कारणों से यह पेश नहीं किया जा सका था।

सरकार निजी विद्यालयों को अब जवाबदेह बनाना चाहती है

अब इस विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करने का दिल्ली मंत्रिमंडल का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शुल्क प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। निजी विद्यालयों को अब जवाबदेह बनना होगा। वे अभिभावकों पर मनमाने तरीके से आर्थिक बोझ नहीं डाल सकेंगे। हैरत की बात तो यह है कि निजी विद्यालयों में

शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों में राशि जोड़कर कई वर्षों से वसूली की जाती रही है। विकास शुल्क के नाम पर अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है। मगर, अब इस पर रोक लग सकेगी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना शुल्क बढ़ाने पर निजी विद्यालयों और दिल्ली शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किए थे। इसमें दोराय नहीं कि बार-बार शुल्क बढ़ाए जाने से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों पर नाहक ही आर्थिक बोझ पड़ता है।

व्यापार

एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश; एविएशन शेयरों में हाहाकार, इंडिगो से लेकर स्पाइसजेट समेत के स्टॉक धड़ाम

सरदार वल्लभभाई पटेल अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के विमान के उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की दुखद घटना की खबर और बाजार में मंदी के बीच गुरुवार को एविएशन कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई।

सरदार वल्लभभाई पटेल अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के विमान के उड़ान भरने के



दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की दुखद घटना की खबर और बाजार में मंदी के बीच गुरुवार को एविएशन कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। बजट एयरलाइन्स इंटरग्लोब एविएशन

(इंडिगो) और स्पाइसजेट के शेयरों में 3.4प्रतिशत तक की गिरावट आई। इंडिगो के शेयर आज इंट्रडे में 3.4 प्रतिशत गिरकर एनएसई पर 5,437.50 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए, जबकि

स्पाइसजेट के शेयर 2.6प्रतिशत गिरकर 44.30 पर आ गए।

अन्य एविएशन शेयरों में भी गिरावट: ताल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर में आज 4प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई और यह

इन शेयरों में भी भारी गिरावट

एविएशन सेक्टर के शेयरों के अलावा, 12 जून को होटल और ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुकिंग कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग सेवाएं देने वाली कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। इविसगो और थॉमस कुक इंडिया के शेयरों में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट आई और ये क्रमशः 181 रुपये और 163 रुपये पर

कारोबार कर रहे थे। टीबीओ टेक के शेयरों में 3 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि महिंद्रा होलिडेज के शेयरों में 2.5 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई। ईज माई ट्रिप और यात्रा ऑनलाइन के शेयरों में मामूली गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। बता दें कि विमान दुर्घटना से हवाई यात्रा को लेकर आशंकाएं बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से शेयरों में गिरावट



उद्योगपति गौतम अडानी ने गुरुवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे के निकट एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख व्यक्त किया। एक्स पर अपने पोस्ट में अडानी ने कहा, +हम एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की त्रासदी से स्तब्ध और बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अकल्पनीय क्षति झेली है। हम सभी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जमीन पर मौजूद परिवारों को पूरा समर्थन दे रहे हैं।+ बता दें कि एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पुष्टि की है कि विमान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने से ठीक पहले पायलट ने मेडे कॉल जारी किया था।

क्या है डिटेल
अडानी समूह ने आश्वासन दिया कि वह गुरुवार को अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 200 से अधिक यात्रियों को ले जा रहे एयर इंडिया के विमान 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चल रहे बचाव और राहत कार्यों का समर्थन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है। एयरपोर्ट के ऑपरटर के तौर पर, अडानी ग्रुप की ग्राउंड टीमें घटनास्थल पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से थीं, जो एयरपोर्ट संचालन, आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं और राष्ट्रीय आपदा टीमों के बीच समन्वय

स्थापित करने के लिए काम कर रही थीं।

प्रभावित परिवारों के लिए आपातकालीन सहायता

लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारी ईंधन से भरा विमान टक्कर के बाद आग की चपेट में आ गया, जिससे विस्फोट और भी तेज हो गया। गांधीनगर से 90 कर्मियों वाली तीन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल टीमों सहित आपातकालीन सेवाओं को घटनास्थल पर भेजा गया। सहायता के लिए वडोदरा से अतिरिक्त टीमों को भी तैनात किया गया। हालांकि, हाताहतों और नुकसान की पूरी सीमा का अभी भी आकलन किया जा रहा है, लेकिन अडानी समूह ने दोहराया कि प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। समूह के प्रवक्ता ने कहा, +ऐसे समय में, हमारी प्राथमिकता परिवारों, अधिकारियों और बचाव दल के साथ खड़े होकर हर संभव मदद प्रदान करना है। दुर्घटना का सटीक कारण अधिकारियों द्वारा जांच के अधीन है और अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही हाताहतों और बचाए गए लोगों की संख्या भी।

एयर इंडिया ने क्या कहा
एयर इंडिया के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की उड़ान संख्या ए-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि करते हुए इस पर गहरा शोक जताया और पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। चंद्रशेखरन एक बयान में कहा, +मैं बहुत दुःख के साथ इसकी पुष्टि करता हूँ कि अहमदाबाद से लंदन के गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या ए-171 आज दुर्घटना का शिकार हो गयी। हमारी शोक संवेदनाएं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिजनों के साथ हैं। इस समय, हमारा ध्यान प्राथमिकता लोगों और उनके परिवारों के लोगों को ढाढस बंधाने पर है।

आईपीओ मार्केट एक बार फिर गुलजार हो गया है। एक के बाद एक, कई कंपनियां आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में लिस्टिंग की योजना बना रही हैं। इसी कड़ी में एमटीआर और इस्टर्न ब्रांड के तहत अपने उत्पादों का डिस्ट्रिब्यूशन करने वाली ओर्कला इंडिया ने आईपीओ लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसके तहत कंपनी 2.28 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी। बता दें कि कंपनी ने इसके लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया है।

2.28 करोड़ शेयरों की बिक्री: ओर्कला इंडिया द्वारा प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से कंपनी के प्रमोटर, अन्य शेयरधारकों द्वारा 2.28 करोड़ शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) है।

मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने गुरुवार 12 जून 2025 को एशियन पेंट्स लिमिटेड के 3,50,00,000 शेयर बेचे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेंट कंपनी के ये शेयर अपने पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई सिद्धांत कमर्शियल्स लिमिटेड के जरिए बेचे हैं। ब्लॉक डील में 2201 रुपये प्रति शेयर के दाम पर ये शेयर बेचे गए हैं। इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू 7703.05 करोड़ रुपये है। एशियन पेंट्स के शेयर गुरुवार को बीएसई में 2218.05 रुपये पर बंद हुए हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास अब भी 87 लाख शेयर

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि इस शेयर सेल के बाद ग्रुप के पास



एशियन पेंट्स के 87 लाख शेयर रहेंगे। शेयरों की यह बिक्री रूटीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हिस्सा है। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, 31 मार्च 2025 को खस तिमाही में सिद्धांत कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास एशियन पेंट्स के 4,69,87,850 शेयर या कंपनी में 4.90 पैसे हिस्सेदारी थी। सिद्धांत कमर्शियल्स के पास अब एशियन

पेंट्स के 87 लाख शेयर बचे हैं। फिलहाल, यह पता नहीं लग पाया है कि इस ब्लॉक डील में किसने शेयर खरीदे हैं।
एलआईसी की एशियन पेंट्स में 8.29प्रतिशत हिस्सेदारी
घरेलू म्यूचुअल फंड्स की एशियन पेंट्स में 5.67 पैसे हिस्सेदारी है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल की पेंट कंपनी में 1.24 पैसेट, एसबीआई म्यूचुअल फंड

की 1.51 पैसेट हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी का यह डेटा 31 मार्च 2025 तिमाही तक का है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी की एशियन पेंट्स में 8.29 पैसेट हिस्सेदारी है। एलआईसी के पास एशियन पेंट्स के 7,94,75,946 शेयर हैं। अगर छोटे रेटेल शेयरहोल्डर्स की बात करें तो एशियन पेंट्स में उनकी हिस्सेदारी 11.84 पैसेट हिस्सेदारी है। एशियन पेंट्स के शेयरों में पिछले एक साल में 23 पैसेट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले पांच साल में कंपनी के शेयर 35 पैसेट उछले हैं। एशियन पेंट्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3394 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2125 रुपये है।

नगर में जल भराव, जर्जर भवन व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की चिंता करें

ग्रामीण सर्वे में जमीनी स्तर पर स्वच्छता की प्रगति का होगा आंकलन

कलेक्टर श्री मीना ने स्वच्छता सर्वेक्षण-2025 की तैयारियों की समीक्षा की

बालाघाट । राष्ट्रबाण

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण फेज दो के अंतर्गत चिन्हित मात्रात्मक और गुणात्मक मानकों के आधार पर सभी प्रदेशों एवं जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग प्रदान की जाएगी। इसमें पेयजल व स्वच्छता के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के सम्बंध में गुरुवार को कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने ग्रामीण व शहरी दोनों निकायों की संयुक्त बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की।

कलेक्टर श्री मीना ने ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे की तैयारियों के सम्बंध में निर्देश दिए हैं कि जो भी प्लांट के प्रस्ताव शेष है, जल्द ही तैयारी करें। वहीं बड़ी पंचायतों में सेमिगेशन व कचरा संग्रहण को नियमित रखें। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में सफाई सम्भव नहीं हो पाती है, वहां अभियान के तौर पर जुट जाएं। ग्रामों में सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई पर भी फोकस किया जाए। उन्होंने नगरीय



परिवारों की संख्या के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, मल-जल प्रबंधन पर होगा फोकस

राज्य स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण इकाई द्वारा सर्वेक्षण सभी 52 जिलों में होगा। सभी ग्रामों का जनसंख्या के आधार पर पर न्यूनतम 20 गांवों का चयन होगा। गांव के 14 परिवारों में 3-3 एससी व एसटी, 8 अन्य परिवार के अलावा 2 ऐसे परिवार जो आईएमआईएस में पंजीकृत नहीं किये गए उनका भी चयन किया जाएगा। इसके

अतिरिक्त चयनित गांवों में न्यूनतम 5 सार्वजनिक स्थलों, निर्मित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाईयां, गोबरधन संयंत्र, मल-जल प्रबंधन संयंत्र एवं स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग स्थल शामिल होंगे। जिलों की रैंकिंग का निर्धारण 1000 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। सिटीजन फीडबैक के 100, सर्विस लेवल प्रगति

240, प्रत्यक्ष अवलोकन के 540 और संयंत्रों का निरीक्षण 120 अंक निर्धारित किये गए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, सहायक कलेक्टर श्री आकाश अग्रवाल, प्रभारी डूडा श्री राहुल नायक, सीएमओ श्री बीडी कतरोलिया व अन्य निकायों के सीएमओ तथा सीईओ गूगल मीट से जुड़े।

निकायों को निर्देश दिए हैं कि अगस्त तक विभाग द्वारा निर्धारित कार्यों पर फोकस होकर कैलेंडर अनुसार कार्य करें। खास

तौर पर नगर के उन क्षेत्रों को चिन्हित कर कार्य करें, जहां जल भराव होता है और यातायात बाधित भी होता है, जर्जर भवनों

को लेकर तैयारी कर लेंगे। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों के सम्बंध में तैयारी कर ले।

अवैध शराब पर आबकारी विभाग की कार्यवाही

डिब्बों में भरा 225 किलो लाहन किया जब्त



बालाघाट । राष्ट्रबाण

के डिब्बों में भरा हुआ लगभग 225 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर 01 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया। वहीं सम्पल लेकर शेष लाहन मौके पर नष्ट किया गया। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 22500 रुपये बताया गया है। इस कार्यवाही में वृत्त प्रभारी संदीप श्रीवास, आरक्षक नरसिंह टेकाम, भानु प्रताप एवम अनिता कुमरे उपस्थित रहे।

कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी सुरेन्द्र कुमार डांव के मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि गुरुवार को आबकारी वृत्त वारासिवनी के द्वारा ग्राम खमरिया के गारापुरी में अलग-अलग स्थानों से प्लास्टिक

1 साल से कर्तव्य पद से नदारद पटवारी कई बार नोटिस जारी करने के बाद एसडीएम ने जारी की सार्वजनिक सूचना

बालाघाट । राष्ट्रबाण

बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता ने बिरसा तहसील के पटवारी कुलदीप मेरावी को कार्य पर उपस्थित न होने पर सार्वजनिक सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि श्री कुलदीप मेरावी पटवारी तहसील बिरसा 13 सितंबर 2024 से बिना पूर्व सूचना अथवा स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित हैं। उन्हें पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने न तो जवाब प्रस्तुत किया और न ही कार्य पर उपस्थित हुए। अब उन्हें सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी

पीएम जनमन एवं धरती आबा के शत प्रतिशत सेचुरेशन के लिए प्रशासन की सक्रियता

बालाघाट । जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय अभियान (पीएम जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत 15 से 30 जून तक जागरूकता एवं लाभ संतुषि शिविर आयोजित किया जाना है। जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त प्रेस नोट में बताया गया कि जिले में पीएम जनमन के तहत चिन्हित 260 बैगा बसाहटों / ग्रामों में तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूप) अंतर्गत

चिन्हित 200 ग्राम एवं जिले के द्वारा सर्वे पश्चात चयनित 48 ग्रामों में जनजागरूकता एवं लाभ संतुषि शिविर का आयोजन 15 जून से प्रारंभ किया जा रहा है। जिले में अभियान अंतर्गत ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित कराकर प्रशासनिक अमले के द्वारा हितग्राही मूलक योजनाएं यथा आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पी.एम. किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्जवला योजना, राशन कार्ड, जनधन बैंक खातों से लाभार्थी किया जायेगा।

राजस्व बैहर में उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। यदि वे निर्धारित समयावधि में कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं तो नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और उन्हें सेवा से पृथक किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

मप्र नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार दो दिन के बालाघाट प्रवास पर

बालाघाट । मप्र नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार 13 एवं 14 जून दो दिन के बालाघाट प्रवास पर होंगे। उनके निर्धारित कार्यक्रम अनुसार वे शुक्रवार सुबह 5 बजे जिला धार से इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे।

सुबह 6 बजे इंदौर एयरपोर्ट आगमन के बाद वे बाय प्लेन नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 8:05 बजे नागपुर आगमन के पश्चात करीब 9 बजे बाय रोड भंडारा तुमसर होते हुए करीब 11:30 बजे नेता प्रतिपक्ष श्री सिंधार बालाघाट जिले की तहसील कटंगी पहुँच जनसामान्य से भेंट सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात वारासिवनी में जनसामान्य से भेंट कर करीब 2:30 बजे बालाघाट के सर्किट हाउस पहुँचेंगे।

अटल पेंशन योजना का लक्ष्य हासिल करने में बालाघाट देश में द्वितीय

प्रशासन की प्लानिंग रंग लायी, जरूरत के समय मिलेगी राशि

बालाघाट । राष्ट्रबाण

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल अटल पेंशन योजना में लक्ष्य से अधिक पात्र नागरिकों को योजना में पंजीयन करने के मामले में बालाघाट ने बड़ा नाम हुआ है। पूरे देश में बालाघाट द्वितीय स्थान पर है। इस वित्तीय वर्ष में पूरे देश के जिलों के लिए पेंशन निधि वित्तीयमक और विकास प्राधिकरण द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

इस लक्ष्य को बालाघाट ने शत प्रतिशत नहीं बल्कि दो गुना अधिक प्राप्त किया है। लीड बैंक मैनेजर श्री संजीव कुमार ने बताया कि 1 मई से 15 जुलाई तक कि स्थिति के लिए वित्तीय वर्ष का लक्ष्य निर्धारित रहता है। जो सभी जिलों के लिए निर्धारित होता है। बालाघाट में कलेक्टर मृणाल मीना ने निर्देशन में अप्रैल में ही राष्ट्रीय बीमा योजनाओं में अभियान के रूप में लिया गया। बालाघाट को 2992 का लक्ष्य दिया गया था। हमने निर्धारित लक्ष्य से दो गुना से अधिक यानी 6141 बैंक खातें पंजीयन किये हैं। यह 205 प्रतिशत है। नियामक ने टॉप टेन जिलों की सूची जारी की है। सूची के अनुसार मप्र में बालाघाट ने लक्ष्य हासिल कर प्रथम पायदान पर है। के उज्जैन



जैसे जिले से बालाघाट आगे निकला है।

इस उपलब्धि में तीन विभागों की अहम भूमिका

जिले में अप्रैल माह से ही राष्ट्रीय बीमा योजनाओं में पात्र नागरिकों का पंजीयन कराने का बड़ा काम हाथ में लिया था। इस काम को मुख्य रूप से महिला बाल विकास विभाग के अलावा वित्त (बैंक),

पंचायत विभाग की बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

यह भी जानें क्या है ?

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना पूरे देश में खाताधारकों के बैंक खातों से ही जुड़ती है। इसमें सिर्फ बैंक को राजीनामा देना होता है। इस राजीनामा से आपके खाते से ही उम्र के हिसाब से न्यूनतम मासिक क्रिस्त कांटी जाती है। इसके पश्चात 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित रूप से उसी बैंक खातों में मासिक राशि प्राप्त होगी। यह मासिक राशि 1000 से 5000 रुपये तक मासिक पेंशन प्राप्े त हो सकती है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान जट्टा और कोपे में 70 मछली पालकों के बनाये केसीसी कार्ड

31 सदस्यों को 3.10 लाख के ऋण स्वीकृति प्रदान की

बालाघाट । राष्ट्रबाण

विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में किसानों को तकनीकी सलाह के साथ ही योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इस अभियान में जर जनपद की दो-दो पंचायतों में शिविर/कार्यशालाएं आयोजित की जा रहें हैं। जिला मत्स्य अधिकारी श्रीमती पूजा रोडगे ने बताया कि अभियान में शिविरों के माध्यम से मछुआ कल्याण समितियों के केसीसी कार्ड बनाने के साथ ही समितियों के सदस्यों को केसीसी का लाभ भी दिया जा रहा है।



गुरुवार को अभियान के दौरान ही बैहर जनपद की जट्टा पंचायत की मछुआ सहकारी समिति के 31 सदस्यों को केसीसी कार्ड के तहत 3.10 लाख रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किये गए हैं। इसी तरह जट्टा में 31 व लालबर्ग

जनपद के कोपे में 39 केसीसी कार्ड बनाये गए हैं। जट्टा की मछुआ समिति के गेंदालाल, ब्रजलाल, दिलीप, चन्दनवार, राजेन्द्र, शिवलाल व अशोक सहित 31 सदस्यों को स्वीकृति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं।

बालाघाट । राष्ट्रबाण

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में गुरुवार को ग्राम पंचायत जागपुर (रेंगाटोला) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित श्री जीतेन्द्र मोहन धुर्वे जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामीणजनों को नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए



विधिक सेवाएं योजना 2015, मोटरयान अधिनियम के प्रावधान,

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के

बारे में अवगत कराया साथ ही मध्यस्थता योजना एवं भारतीय

संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही श्री धुर्वे ने न्यायालयीन प्रक्रिया एवं साइबर अपराधों से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में पाक्सो अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया।

शिविर में ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव, पैरालीगल वालेटियर श्रीमती नन्दिनी बोरकर, जिला प्राधिकरण के कर्मचारी श्री धनेन्द्र उपराड़े, विधि छात्रा सुश्री फाल्गुनी बाहे, श्री उत्कर्ष राहंगडाले एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

प्रशासनिक सर्जरी से नहीं बच पाए विवादित प्रभारी तहसीलदार

डॉ. संजय बरैया की कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा उठते हैं सवाल

सिवनी। राष्ट्रबाण

जहां कुछ अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आम जनता की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। इससे न केवल विभाग की छवि धूमिल होती है। ऐसा ही मामला लखनादौन तहसील के प्रभारी तहसीलदार जो हमेशा विवादित कार्य प्रणाली के आरोप से जाने जाते है। जिनके चलते सरकारी कामों को करवाने के नाम पर दलालों से सहयोग लेते रहे हैं।

यह मामला तब जोरो से उछला जब संजय बरैया की पदस्थापना बरघाट प्रभारी तहसीलदार के रूप में थी। इनकी विवादित कार्य प्रणाली और भ्रष्टाचार की चर्चा बरघाट में ही नहीं पूरे जिला मुख्यालय में फैली हुई थी। इन्होंने अपनी तहसीलदार



संजय बरैया, प्रभारी तहसीलदार।

पद की शक्तियों का गलत उपयोग करते हुए दलालों के माध्यम से धन लेकर उल्टे सिधे प्रकरण में आदेश किया है। जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी तब बरघाट से लखनादौन स्थानांतरण कर दिया था। लेकिन जैसे ही इनकी कार्यप्रणाली के चर्चे राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल

तक पहुंचने लगे तब स्थानांतरण वक्त के दौरान अवर सचिव राजस्व विभाग द्वारा प्रशासनिक स्तर से संजय बरैया का स्थानांतरण सिवनी लखनादौन से भिंड कर दिया लगभग 720 किलोमीटर दूर स्थानांतरण के आदेश से डॉ. संजय बरैया की रात की नींद उड़ गई है। चेहरे पर

परेशानी दिन में नजर आ रही है। सूत्र तो यहां भी बता रहे हैं कि संजय बरैया अपने स्थानांतरण को रूकवाने के लिए अपने रुदवे पैसों का पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में तहसील लखनादौन में देखकर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर का न्याय सबके लिए एक समान है, कर्मों का फल इसी

कर्मचारी भी थे परेशान

जहां-जहां डॉ. संजय बरैया की पदस्थापन रही है वहां-वहां कर्मचारी भी परेशान रहे है, लगातार कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना देना। साथ ही सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते थे जब वह बरघाट तहसीलदार के पद में थे तब उनके द्वारा अवकाश के दौरान अपने मूल निवास लालबरां जाने के लिए वह सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और गाड़ी की लोक बुक में अपने कार्यक्षेत्र का दौरा दिखा दिया जाता था।

कैसे होता है था खेल?

सूत्रों के अनुसार, तहसीलदार ने अपने विश्वासी कर्मचारी और लोगो को दलाली की खुली मंजूरी दे दिया था। जिसमें तहसीलदार द्वारा दलालो को पूरा सहयोग भी मिल रहा था। दलाल इन अधिकारियों से संपर्क करके फाइलों को जल्दी निपटाने का वादा करते थे और इसके बदले पर मोटी रकम की मांग करते थे। यह भ्रष्टाचार का खेल आम नागरिकों के लिए भारी परेशानी का कारण बनता था। क्योंकि बिना दलालों के माध्यम से अपनी जरूरी सरकारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर सकते थे। उदाहरण के तौर पर, जमीन का नामांतरण, पारिवारिक सहमति से बटवारा, नक्शे और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए तहसीलदार द्वारा कर्मचारी एवं दलालों के मध्यम से रिश्तत की मांग की जाती थी। कर्मचारी एवं दलालों से पैसे लेने के बाद ही तहसीलदार संबंधित कार्य की कोई कार्यवाही करते थे और प्रकरण को जल्दी निपटाते थे। वहीं तो तारीख पर तारीख देकर कार्यालय के चक्कर लगावते थे, जो कि आम लोगों के लिए परेशानी बन गई थी।

जन्म में भोगना पड़ेगा।

मानो या ना मानो...

आखिर क्या वजह है जो जाता है जियारत वह परेशान हो जाता है?



सिवनी। राष्ट्रबाण

जी हां..! आपने सही पड़ा जो जाता है, वह परेशान हो जाता है। यह बात गौर करने वाली भी है। जिला मुख्यालय अंतर्गत पटवारी हल्का जियारत सबकी जुबान पर है आखिर क्या वजह है? जो भी पटवारी यहां बेईमानी से अर्जित कमाई करने के उद्देश्य से जाता है। या तो वह बीमारी का शिकार हुआ यह फिर भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। और इससे सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि यहां पर बनी नई कॉलोनी के कॉलोनाइजर भी किसी न किसी पीड़ा से प्रताड़ित हो चुके

है। आखिर क्या है इसकी वजह? इसे कहीं न कहीं यह कुदरत का करिश्मा कहे या अलौकिक शक्ति कोई इशारा तो नहीं, यह विचार की बात है। आज दिनांक में सिवनी तहसील कार्यालय में जियारत हल्का की चर्चाओं जोरों से हैं। जो भी पटवारी जियारत हल्का गया है वह बीमारी या फिर भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। मानो या ना मानो या, यह बात कुछ हद तक सही भी है। जियारत किसी को रास नहीं आया है तो किसी को उनके कर्मों का हिसाब भी इसका फल मिला है।

कब होगा देवी तालाब अतिक्रमण मुक्त ? नपा के साटगांट से बढ़ रहा अतिक्रमण का दायरा



बालाघाट। राष्ट्रबाण

नगर मे स्थित शासकीय देवी तालाब जो कि बालाघाट शहर के भूमिगत जल स्रोत का मुख्य साधन है और यह तालाब बालाघाट शहर के नागरिकों का निस्तार तालाब है। इस तालाब मे बालाघाट के नगरवासी द्वारा धार्मिक प्रयोजन मे दुर्गा प्रतिमा विषर्जन, गणेश प्रतिमा विषर्जन, भुजली विषर्जन, ताजिया विषर्जन समेत अन्य धार्मिक प्रयोजन किए जाते है। प्राचीन काल से ही शासकीय देवी तालाब बालाघाट शहर के नागरिकों के धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन आज देवी तालाब लगातार अपने अस्तित्व को खोते जा रहा है। जिसके पीछे बालाघाट के भू-माफियाओ की कारगुजारी शामिल है। बालाघाट शहर के भू माफियाओ द्वारा नगर पालिका

परिषद बालाघाट के साथ मिलकर देवी तालाब के अस्तित्व को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्र के तहत नगर पालिका परिषद द्वारा नगर क्री नालियों मे बहने वाले दूषित मलजल युक्त प्रदूषित पानी को छोटी छोटी नालियों एवं बड़े नालो के माध्यम से सीधे देवी तालाब मे छोड़ा जा रहा है। जिससे देवी तालाब लगातार प्रदूषित हो रहा है और नगर पालिका द्वारा वार्डों से जमा किए गए कचरे को देवी तालाब मे डालकर तालाब को भरने का कार्य किया जा रहा है।

शासकीय देवी तालाब मे नगर पालिका परिषद द्वारा किए जा रहें प्रदूषण को रोकने एवं तालाब क्री साफ सफाई किए जाने को लेकर बालाघाट शहर निवासी द्वारका नाथ चौधरी एवं अन्य जागरूक नागरिकों के द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया।

बालश्रम के खिलाफ दुकानदारों को दी गई सख्त चेतावनी जस्ट राइट नेटवर्क और प्रदीपन की बड़ी भूमिका

बैतूल। राष्ट्रबाण

जिले को बालश्रम मुक्त बनाने के लिए एक संगठित और प्रभावशाली अभियान की शुरुआत हो चुकी है। विश्व बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर सक्रिय नागरिक संगठन प्रदीपन ने श्रम विभाग, पुलिस विभाग और टास्क फोर्स के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर 100 बालश्रमिक बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया।

इस मौके पर प्रदीपन संस्था की डायरेक्टर रेखा गुजरे ने बताया कि पिछले एक वर्ष में जिला प्रशासन के सहयोग से बालश्रम के खिलाफ अभियान चलाकर 26 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। आज की कार्रवाई में भी अनेक होटलों, ढाबों, मोटर गैराज, ईटभट्टों और दुकानों पर छपा मारा गया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि वे 18 वर्ष से कम उम्र के



दुकानों पर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाने के निर्देश

जिला मुख्यालय पर भी गुरुवार को बालश्रम उन्मूलन अभियान संचालित किया गया। दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी दुकानों पर स्पष्ट रूप से यह बोर्ड लगाएं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर नहीं रखा जाता। टास्क फोर्स टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया और समझावशील भी दी। प्रदीपन संस्था देश के सबसे बड़े नागरिक समाज नेटवर्क जस्ट

बच्चों से मजदूरी कराते पाए गए तो बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैतूल जिले में अब तक 32 बच्चों को बाल मजदूरी से छुड़ाया: रेखा गुजरे ने कहा कि भारत ने इस दिशा में अन्य देशों के मुकाबले बेहतर कार्य किया है और इसका श्रेय राज्य सरकार और

जिला प्रशासन की सतर्कता और संवेदनशीलता को जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक बैतूल जिले में 32 बच्चों को बाल मजदूरी से छुड़ाया गया है और उनके पुनर्वास की दिशा में लगातार कार्य जारी है।

उन्होंने यह भी कहा कि बाल मजदूरी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए पुख्ता नीतियां बनानी होंगी

अभियान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका

ऊर्जा स्ट्राइक फॉर चिल्ड्रन के राष्ट्रीय संयोजक रविकांत ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 182 का हस्ताक्षरकर्ता देश है और उसने खतरनाक बाल श्रम को समाप्त करने की प्रतिबद्धता ली है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि बालश्रम मुक्त आपूर्ति श्रृंखला, कौशल विकास और शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। इस अभियान की सफलता में प्रदीपन के कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार, सोशल वर्कर पुनम अतुलकर, चारुलता वर्मा, अलका नागले, ज्योति बागवे, विशाल आर्य, रवि चवारे और राकेश मन्नासे का अहम योगदान रहा। बैतूल जल्द ही बालश्रम मुक्त जिले के रूप में स्थापित हो, इसके लिए नागरिक संगठन और जिला प्रशासन मिलकर सशक्त प्रयास कर रहे हैं।

जैसे कि सरकारी खरीद में बालश्रम का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित किया जाए, 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाए, बाल मजदूर पुनर्वास कोष की स्थापना की जाए और खतरनाक उद्योगों की सूची में विस्तार किया जाए।

सुभाष वार्ड में पार्षद किरण खातरकर ने महिलाओं के साथ उठाई झाड़ू

विधायक की प्रेरणा से शुरू हुआ स्वच्छता अभियान

बैतूल। राष्ट्रबाण

सुभाष वार्ड क्रमांक 1 में स्वच्छता को लेकर एक सकारात्मक पहल की शुरुआत हुई है। वार्ड की पार्षद किरण खातरकर ने विधायक हेमंत खंडेलवाल की प्रेरणा से स्वच्छता अभियान की कमान संभालते हुए वार्डवासियों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। वार्ड के पीपल चौराहे पर फैली गंदगी को देखते हुए पार्षद के नेतृत्व में वार्ड की महिलाओं ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की और पूरे क्षेत्र में स्वच्छता का संदेश दिया। इस स्वच्छता अभियान में बड़ी संख्या में महिलाएं और वार्डवासी



शामिल हुए। अभियान के दौरान पार्षद किरण खातरकर ने बताया कि विधायक हेमंत खंडेलवाल की प्रेरणा से वार्ड में साप्ताहिक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, जो निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाकर

उनकी समस्याओं को भी समझा जाएगा। साथ ही वार्ड में अगर कोई अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो उन पर अंकुश लगाने का भी प्रयास किया जाएगा।

पार्षद खातरकर ने यह भी बताया कि विधायक खंडेलवाल के सहयोग से वार्ड का समग्र विकास

लगातार जारी है और यह प्रयास आगे भी चलता रहेगा ताकि सुभाष वार्ड को नगर में स्वच्छता और विकास के क्षेत्र में नंबर एक स्थान प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि वार्डवासियों, विशेषकर महिलाओं में भाजपा के कार्यकाल में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उत्साह है

और अब स्वच्छता को लेकर भी सभी पूर्ण रूप से तैयार हैं।

स्वच्छता अभियान में वार्ड की प्रमुख महिलाएं निशा मेहरा, कविता बरसाकर, मुन्नी यादव, जमना महाजन, चंदा मोहबे, उर्मिला मवासे, लता परिहार, रेवती बिनझाड़े, जमना चतुरकर शामिल रहीं। इनके साथ ही विनोद यादव, देवीनाथ लोखंडे, लक्ष्मीनारायण खातरकर, विशाल भौरासे, सफाई कर्मी गोविंद सांडे, पिकी जावलकर, किशोर उईके, पवन वाड्डिया, गुड्डी यादव, सुनील पाल और गोलू चिंचलकर समेत बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे।

बैतूल। राष्ट्रबाण

तहसील शाहपुर के ग्राम कछार जोडियामऊ निवासी रमेश पिता जगलू लोखंडे ने कलेक्टर को आवेदन देकर अपने पिता की मृत्यु के बाद मिलने वाली सहायता राशि दिलवाने की मांग की है। रमेश ने अपने शिकायती आवेदन में बताया कि उनके पिता जगलू लोखंडे की अचानक मृत्यु 8 फरवरी 2025 को हो गई थी। लेकिन अब तक शासन से मिलने वाली 5000 रुपये की सहायता राशि नहीं मिली है। रमेश ने कहा कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है

और इस सहायता राशि से कुछ राहत मिल सकती है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद मिलने वाली निर्धारित सहायता राशि उन्हें जल्द से जल्द दिलवाई जाए, ताकि वे परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें। रमेश का कहना है कि उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं, इसके बावजूद उन्हें अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन उनकी बात को गंभीरता से लेकर जल्द राहत प्रदान करेगा।

